सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

1-15 सितंबर, 2023 वर्ष-1 अंक-11

निःशुल्क प्रति

पूरी दुनिया में

भारत का डंका

दूरदर्शी कूटनीति है नए भारत का सामर्थ्य

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

पूरी दुनिया को भारत ने दिया शांति का संदेश	11
दूरदर्शी कूटनीति है नए भारत का सामर्थ्य	12
आगे बढ़ी है भारत-सऊदी अरब साझेदारी	14
मेहमानों ने की भारत की प्रशंसा	16
कंधे से कंधा मिलाकर हम करते हैं काम	20
अधिक लोकोपयोगी बन रही है राजभाषा	22
अमृत काल में बेहतर होती सेवाएं	25
गेस्ट कॉलम	26

विशेष रिपोर्ट

05 पूरी दुनिया में भारत का डंका

18 भारत का बढ़ा कद

21 स्कूलों में संस्कृति और विविधता का जश्न मनाएं

संपादक की कलम से...

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> जी20 की भारतीय अध्यक्षता सच्चे अर्थों में जन-केंद्रित रही और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी है। नई दिल्ली में जब वैश्विक नेताओं का जुटान हुआ, तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता, श्री अमित शाह जी के कुशल निर्देशन में सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई।

'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का सूत्र देते हुए भारत ने पूरी दुनिया के सामने नया आयाम गढ़ा है। भारत ने इंडोनेशिया के बाली में मिली जी20 की अध्यक्षता से लेकर नई दिल्ली के घोषणापत्र तक अलग-अलग विभागों और समूहों की सैकड़ों बैठकों के माध्यम से पूरी दुनिया को यह दिखाया कि समावेशी सोच के साथ कैसे समेकित विकास के लिए सधे हुए कदम बढ़ाए जाते हैं। अफ्रीका को जी20 के समूह में शामिल कराकर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने भारत की कूटनीतिक रणनीति का झंडा गाड़ दिया है। नई दिल्ली में आयोजित जी20 की बैठक में घोषणापत्र का सर्वसम्मति से पास होना नए भारत के सामर्थ्य एवं कुशल कूटनीति को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री जी के जन भागीदारी वाले दृष्टिकोण ने जी20 के कार्यक्रमों और गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों को शामिल किया। 60 शहरों में हुई 200 से अधिक बैठकें, जी20 के कार्यक्रमों को लेकर लोगों की एक अभूतपूर्व भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके फलस्वरूप, जी20 की भारतीय अध्यक्षता सच्चे अर्थों में जन-केंद्रित रही और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी है। नई दिल्ली में जब वैश्विक नेताओं का जुटान हुआ, तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता, श्री अमित शाह जी के कुशल निर्देशन में सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई। किसी भी मेहमान को पल भर के लिए भी कोई असुविधा नहीं हुई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में बेहतर समन्वय का यह उदाहरण सभी ने देखा।

भारत ने पहली बार जी20 के मंच पर साइबर सुरक्षा की बात जुलाई महीने में की थी। सितंबर में दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद और वैश्विक भ्रष्टाचार को खत्म करने के भारत के आह्वान पर सभी देशों ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। नई दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से पारंपरिक विरासत को संभालने तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के तीव्र प्रसार के प्रयासों पर भी भारत की पहल को स्वीकारता मिली है। सभी ने माना कि सृजनात्मकता, तर्कसंगत सोच, अनुसंधान, कौशल विकास, उद्यमिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर हम नूतन लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे।

'सजग भारत' का 11वां अंक आपके हाथों में है। ई-संपर्क के माध्यम से हमारी पहुंच अब सात करोड़ से अधिक नागरिकों तक हो गई है। आपके सुझाव हमें प्राप्त होते हैं, यह हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहें। हमारा ई-मेल है : sajag-bharat@bprd.nic.in

जय हिंद!

भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर किस प्रकार अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है, इसका एक बड़ा उदाहरण जी 20 समिट के दौरान देखने को मिला है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

Expressing unanimous support for PM Shri Narendra Modi Ji's vision of 'One Earth One Family One Future,' the G20 leaders made a historic decision by including the African Union as a permanent member of this prestigious global organisation.

Shri Amit Shah
Union Home Minister and Minister of Cooperation

ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज-3 को भी मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत अदालतों को ऑनलाइन किया जाएगा। जिससे न्यायिक प्रणाली को जनता के लिए और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

The showcasing of rich culture from our heritage to cuisines to dresses to handicrafts has made every Bharatiya proud. Be it the depiction of the Konark Sun Temple or Nalanda University, the imagery captured the minds of people around the world.

Shri Nisith Pramanik
MoS, Ministry of Home Affairs

हिंदी महज एक भाषा नहीं, अपितु हमारे जीवन मूल्यों, संस्कारों तथा राष्ट्रीय एकता का बोध कराने वाली पूरी संस्कृति है।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक, प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

पूरी दुनिया में भारत का डंका

'भारत इस बात के लिए गर्व करेगा कि जब भारत जी-20 का अध्यक्ष रहा, तब अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना'

ब्यूरो

बहुप्रतिक्षित जी 20 की दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। नई दिल्ली में 9-10 सितंबर को हुए इस समारोह को यदि महाशक्तियों का महापर्व कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' नारे के तहत हुए सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी दक्षिणी गोलार्द्ध के गरीब देशों के प्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं। मेजबान भारत के प्रयासों से पश्चिमी देशों और रूस के बीच विवादों के बावजूद अंतिम घोषणा पर सहमति हो गई।

इसे सम्मेलन की बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों के इस समूह के नेताओं ने शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर पर्यावरण सुरक्षा और गरीबी जैसे मुद्दों पर मिल-जुलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। इसे भी सरकार की सफलता कहा जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति, श्री जो बाइडेन ने सम्मेलन की कामयाबी के बारे में कहा कि इसने ये साबित किया है कि मुश्किल आर्थिक समय में भी जी20 फौरी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। यह अनायास नहीं था कि जर्मनी के चांसलर, श्री ओलाफ शॉल्त्स ने सम्मेलन की भावना की तारीफ करते हुए कहा था कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक नए तरह का संवाद, ये नई दिल्ली के सम्मेलन में संभव हुआ। सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति, श्री व्लादिमीर पुतिन का प्रतिनिधित्व करने वाले रूसी विदेश मंत्री, श्री सेर्गेई लावरोव ने सम्मेलन के नतीजों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज पश्चिम ने विश्व में वर्चस्व खो दिया है और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का महत्व बढ़ा है। यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि नए वैश्विक केंद्र उभर रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, तो पश्चिम प्रभुत्वशाली नहीं रह सकता।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी दो दिनों के सम्मेलन में पूरे उत्साह से लबरेज थे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने एकमत से स्वीकार कर लिया है। भारतीय विदेश मंत्री, डॉ एस जयशंकर ने और जी20 शेरपा, श्री अमिताभ कांत ने मीडिया को आधिकारिक रूप से बताया कि जी20 सम्मेलन में सभी देशों के सहयोग से नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। इसका मतलब है कि अब भारत वैश्विक पटल पर अपना स्थान पा चुका है। इस घोषणा पत्र को बिना एक भी फुटनोट के स्वीकार किया गया है। आज की दुनिया में प्लेनेट, पीपुल, पीस एवं प्रोस्पेरिटी का आह्वान है जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी दुनिया के नेता बन चुके हैं। जो आखिर में होना था, वह पहले दिन ही हो गया।

गौर करने योग्य यह भी है कि जी20 सम्मेलन में एक मेगा प्लान

जी20 की सफलता है 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय देश की समस्त जनता को देते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की सफलता नहीं है। लोकसभा में 'संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा' उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख' विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि यह हर किसी के लिए जश्न की बात है। उन्होंने कहा कि जी20 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की सफलता है, किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की नहीं। भारत की क्षमताओं के बारे में संदेह पैदा करने की कुछ लोगों की नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जी20 घोषणा पत्र के लिए सर्वसम्मति और भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत की जी20 अध्यक्षता नवंबर के अंतिम दिन तक है और राष्ट्र इसका पूरा उपयोग करने का इरादा रखता है, प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में पी20 शिखर सम्मेलन (संसदीय 20) आयोजित करने के अध्यक्ष के संकल्प का समर्थन किया।

सभी जानते हैं कि भारत के पास नवंबर 2023 तक जी20 अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है। इन दो दिनों में आप सभी ने बहुत सारे सुझाव दिए और प्रस्ताव रखे। यह हमारा कर्तव्य है कि हमें जो सुझाव मिले हैं, उनकी एक बार फिर से समीक्षा की जाए, ताकि यह देखा जा सके कि उनकी प्रगति को कैसे गति दी जा सकती है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

का ऐलान किया गया। ऐलान ऐसा जिससे दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा भी लग गया। एक फैसला भारत के कई दुश्मनों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। खासकर चीन और पाकिस्तान पर इसका खासा असर होगा। अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा कर दी। जी20 समिट के पहले दिन इंडिया मीडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि इन्फ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी। इससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। सदस्यों ने विकासशील देशों में निवेश परियोजनाओं हेतु निजी क्षेत्रों की भूमिका को रेखांकित किया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता दूर करने एवं टिकाऊ, संतुलित, सर्वसमावेशी, दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता हेतु व्यापक आर्थिक एवं संरचनात्मक नीतियों को लागू करने पर सहमति बनी है। समान विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता की मजबूती से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा होगी। जी20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 'वन अर्थ वन फैमिली' पर प्रमुखता से बात की और मानव केंद्रित विकास की बात करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा से इसे बढ़ावा दिया है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की और कहा, 'कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप के प्रभावित लोगों के लिए संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा विश्व उनके साथ है और हम उन्हें हरसंभव मदद देने को तैयार हैं।'

प्रधानमंत्री ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल, नॉर्थ और साउथ के बीच का फर्क, ईस्ट और वेस्ट के बीच का फर्क, अनाज संकट, खाद संकट जैसी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि आज हम लोग नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका सामना करना ही पड़ेगा।

अफ्रीकी संघ को जी20 का सदस्य बनाने संबंधी प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का प्रस्ताव इस प्रभावशाली समूह के सभी सदस्य देशों ने शनिवार को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ ग्लोबल साउथ का यह प्रमुख समूह दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा कि आप सभी के समर्थन से, मैं अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष अजाली असौमानी को जी20 मंच की मेज पर उनकी सीट तक ले गए।

यकीनन, जी20 में भारत की इस कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री का कद और बड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के लिए यह बात

वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ

'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 जनवरी, 2023 को हुआ। भारत की अध्यक्षता का यह एक अनूठा पहलू था। इन सबके बीच एक विशेष संतुष्टि की बात यह है कि भारत की पहल के चलते अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने समकालीन प्रौद्योगिकी के मामले में भारत की प्रगति और साथ-साथ हमारी विरासत, संस्कृति और परंपराओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया। जी20 के सदस्य देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने इसकी व्यापक तौर पर सराहना की।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि चाहे नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार करने की बात हो या अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की इस शिखर सम्मेलन ने श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के दृष्टिकोण पर खरा उतरने वाले देशों के बीच विश्वास के पुल का निर्माण किया है। शिखर सम्मेलन हमारे देश के हर नागरिक के लिए एक अमिट छाप छोड़ गया है।

कितनी अहम रखती है, उसका संकेत दूसरे सत्र के समय तब दिखा, जब उन्होंने बेहद खुशी और संतोष की मुद्रा में सहमति बनने का ऐलान किया। दरअसल, भारत पर दोनों ओर से बहुत दबाव था, लेकिन इस दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय देश बार-बार यूक्रेन को भी सम्मेलन में बुलाने का दबाव बना रहे थे। उनका यही कदम रूस और चीन को मनाने में काम आया।

शीर्ष नेताओं ने जलवायु मोर्चे सहित विश्व के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल पहल करने का आह्वान किया। निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध वैश्विक मुहिम के लिए व्यापक रणनीति जैसे इस हेतु वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने आदि पर सहमति बनी है। आतंकवाद एवं वैश्विक भ्रष्टाचार को खत्म करने, पारंपरिक विरासत को संभालने तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के तीव्र प्रसार के प्रयासों पर भी भारत की पहल को स्वीकार्यता मिली है। भारत ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सर्वथा सक्षम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिवर्तनकारी पहलुओं से सदस्य देशों को परिचित करवाया। सभी ने माना कि शिक्षा में सृजनात्मकता, तर्कसंगत सोच, अनुसंधान, कौशल विकास, उद्यमिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर शिक्षा के नूतन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री ने समापन सत्र में भविष्य की बातें की और भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उनका कहना था कि जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक जी20 प्रेसीडेंसी की जिम्मेदारी है। अभी ढाई महीने बाकी हैं। इन दो दिनों में, आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं, उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में जी20 समिट का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। ■

जी20 शिखर सम्मेलन की खास बातें

- जी20, 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है। अब इसमें अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। वर्ष 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जा सके।
- जी20 की पहली बैठक वर्ष 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। भारत ने इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी की है।
- वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा है। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। इस मंच से वर्ष 2023 में पहली बार साइबर सुरक्षा को लेकर बात की गई।
- जी20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85 फीसदी जीडीपी, 75 फीसदी ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है।
- अफ्रीकी संघ जी20 संगठन में शामिल हुआ और इसी वर्ष से सदस्य बना।
- नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर देश के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अनुसार समावेशी विकास पर जोर दिया जाएगा।
- सदस्य देशों द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस बनाया गया है, जो बायोफ्यूल के अधिकतम उपयोग पर जोर देगा।

भारत की अध्यक्षता में बना अफ्रीकी संघ जी20 का स्थायी सदस्य

ब्यूरो

जी20 की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले मुल्कों के समूह जी20 का स्थाई सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने का ऐलान किया। अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करना एक दूरगामी कदम है। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष श्री अजाली असौमानी को गले लगाया। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत ने 'विश्व मित्र' के रूप में अपनी जगह बनाई है और पूरी दुनिया भारत को एक मित्र के रूप में देख रही है। उसका कारण वेदों से लेकर विवेकानन्द तक से मिले हमारे संस्कार हैं। सबका साथ सबका विकास का मंत्र हमें दुनिया को अपने साथ लाने के लिए एकजुट कर रहा है।

प्रगति मैदान के भारत मंडपम में विश्व नेताओं की तालियों की गूंज के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष श्री अजाली असौमानी को जी20 नेताओं के मंच पर आने का न्यौता दिया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने श्री अजाली असौमानी को इस मंच के नेताओं की मेज पर उनकी सीट तक पहुंचाया। स्थाई सदस्य की सीट पर बैठने से पूर्व अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष श्री अजाली असौमानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बेहद गर्मजोशी से गले मिलते हुए हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके बाद एक्स पोस्ट में कहा कि एक अधिक समावेशी जी20 को आगे बढ़ाना ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अफ्रीकी यूनियन और कोमोरोस के राष्ट्रपति श्री अजाली असौमानी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अफ्रीकी देशों के संघ में अफ्रीका महादेश के 55 देश शामिल हैं और वह लंबे समय से जी20 की सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा था। अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों की जीडीपी लगभग तीन ट्रिलियन अमेरिकी डालर और जनसंख्या करीब 1.4 अरब है। पिछले साल बाली शिखर सम्मेलन में भी अफ्रीकी संघ को निराशा हाथ लगी थी। भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थाई सदस्यता दिए जाने को जी20 में भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विशिष्ट छाप का प्रमाण बताते हुए कहा कि इंडोनेशिया में पिछले वर्ष अफ्रीकी संघ के तत्कालीन अध्यक्ष को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सदस्यता दिलाने का भरोसा दिया था। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अफ्रीकी संघ को जी20 का स्थाई सदस्य बनाकर इस भरोसे को पूरा किया है। ■

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का प्रतीक बनने का भरोसा देता है: प्रधानमंत्री

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जो बाइडेन ने जी20 शिखर सम्मेलन से इतर 9 सितंबर, 2023 को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (पीजीआईआई) और इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) पर हुए एक विशेष कार्यक्रम की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। इस आयोजन का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना और इसके विभिन्न आयामों में संपर्क को मजबूत बनाना है। इस कार्यक्रम में यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के नेताओं के साथ-साथ विश्व बैंक ने भी भागीदारी की।

पीजीआईआई एक विकास संबंधी पहल है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने में मदद करना है। आईएमईसी में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक ईस्टर्न कॉरिडोर और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक नॉर्दर्न कॉरिडोर शामिल है। इसमें रेलवे और जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे।

अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने भौतिक, डिजिटल और वित्तीय संपर्क के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आईएमईसी से भारत और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आईएमईसी से संबंधित एमओयू पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह साझा सहयोग आकांक्षाओं एवं सपनों की यात्रा को विस्तार प्रदान करते हुए सहयोग, नवाचार व साझा प्रगति का प्रतीक बनने का भरोसा देता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि जैसे-जैसे इतिहास सामने आ रहा है, यह गलियारा मानवीय प्रयास तथा महाद्वीपों में एकता का प्रमाण बन सकता है। ■

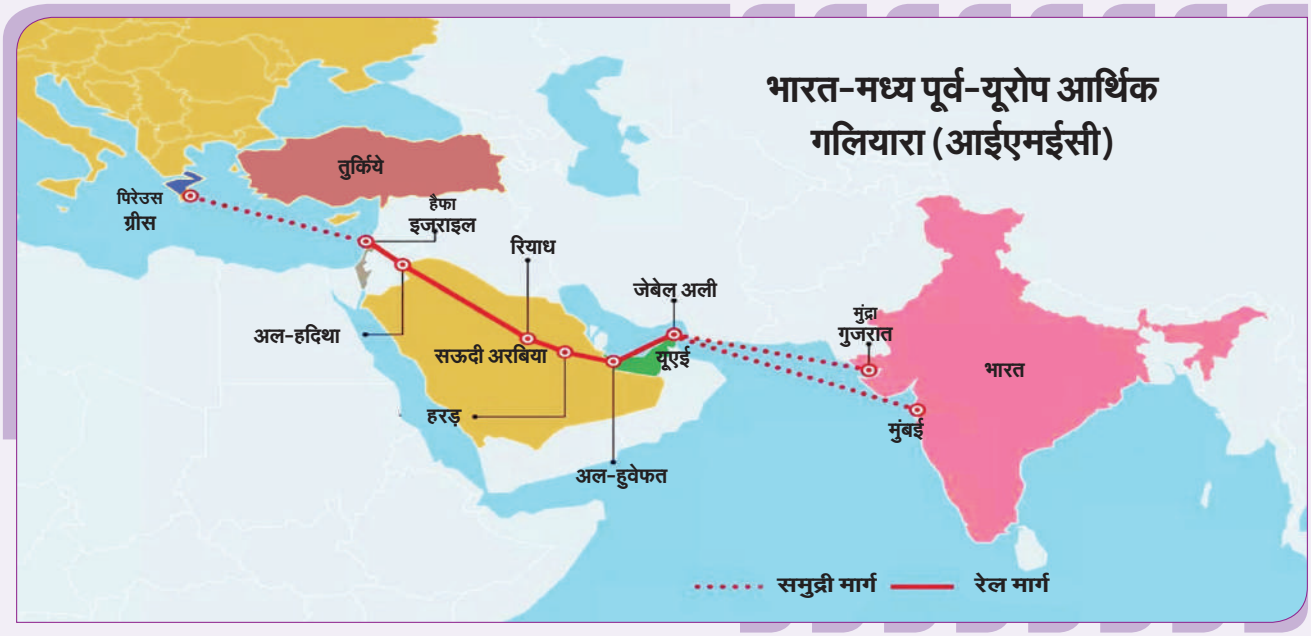

पूरी दुनिया को भारत ने दिया शांति का संदेश

ब्यूरो

शिखर सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी की समाधि पर वैश्विक नेताओं ने जाकर अपनी-अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। उस समय की तस्वीर ने पूरी दुनिया को चमत्कृत किया। दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देशों के मुखिया शांति के प्रतीक महात्मा गांधी की समाधि पर शीश झुकाने जा रहे थे। आगे-आगे भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी चल रहे थे।

राजघाट के दृश्यों में नेताओं के वहां पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया हुआ दिखाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेताओं का स्वागत खादी शॉल और पृष्ठभूमि में गांधी आश्रम के कटआउट के साथ किया। सबसे पहले एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष श्री मासात्सुगु असकावा, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक श्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंचे, प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री अजय बंगा, महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) श्री टेड्रोस एडनोम भी राजघाट पहुंचे। ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमुर अल सैद भी यहां आए। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सीसी, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ भी दिखे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सीन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बानीज, कनाडाई प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी राजघाट पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति श्री यूं सुक येओल, जर्मन चांसलर श्री ओलाफ शोल्ज, तुर्की के राष्ट्रपति श्री रेचेप तैय्यप अर्दोआन, इटली के प्रधानमंत्री श्री जियोर्जिया मेलोनी, रूसी विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री श्री ली कियांग राजघाट पहुंचे। कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष श्री अजाली असौमानी भी राजघाट पहुंचे।

यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामफोसा, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लुइज इनासियो राजघाट पहुंचे। सभी नेताओं ने एक साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद जी-20 के सभी आगंतुक नेता एक साथ बाहर निकले, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन के साथ सबसे आगे दिख रहे थे। ■

> **गांधी जी के शाश्वत आदर्श एक सामंजस्यपूर्ण, समावेशी एवं समृद्ध वैश्विक भविष्य के हमारे सामूहिक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

दूरदर्शी कूटनीति है नए भारत का सामर्थ्य

कुशल नेतृत्व और सशक्त रणनीति होती है, तो हर समस्या का हल आसान ही लगता है। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया और वह सर्वसम्मति से पास हो गया, तो इस तथ्य को सच होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। असल में, यह नए भारत का सामर्थ्य है कि वह अपने हिसाब से नए सूत्र गढ़ता है। नए साथियों को साथ लेकर भविष्य के पथ पर निर्बाध गति से चलने लगता है।

ब्यूरो

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान जब नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसमें मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी से आगे बढ़ने पर अधिक जोर दिया गया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में दीर्घकालिक भविष्य के लिए ग्रीन डेवलपमेंट एग्रीमेंट के साथ 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं को पुनर्जीवित करने पर फोकस है। भारत ने जी20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर शत-प्रतिशत आम सहमति बनने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए कहा कि इससे विश्व में एक मजबूत टिकाऊ, संतुलित एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

आमतौर पर सम्मेलन के आखिरी दिन घोषणा पत्र जारी किया जाता है, लेकिन भारत ने नई राह चुनी। शिखर सम्मेलन के पहले दिन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी पक्षों के बीच सहमति बन गई है। वह इस घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने का ऐलान करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर शेरपा एवं भारतीय अधिकारियों को बधाई दी। इसके कुछ देर बाद ही बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और शेरपा श्री अमिताभ कांत ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को जी20 समूह पर भारत की अमिट छाप वाला एक प्रभावशाली दस्तावेज करार दिया।

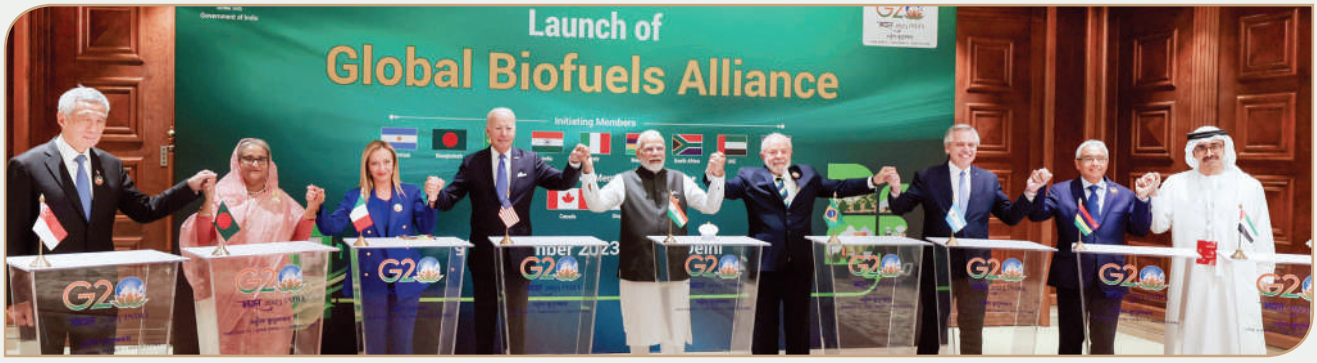

कार्बन उत्सर्जन पर भी सहयोग

नई दिल्ली घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और एक साथ विकास जैसे मुद्दों पर आम सहमति दिखाने के साथ-साथ इसके लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। घोषणा पत्र में पर्यावरण संकटों का भी जिक्र है और इन संकटों से निपटने का जिक्र भी किया गया है। जलवायु परिवर्तन की लगातार आ रही चुनौतियों पर विशेष कार्य योजना की वकालत की गई है। जी20 सदस्य देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा विकासशील देश प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही घोषणा पत्र में पेरिस समझौते पर ध्यान केंद्रित करने और उस दिशा में तेजी से काम करने पर जोर दिया गया है। जी20 के नेताओं ने माना है कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बदलाव के लिए समर्थन की जरूरत है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उनके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जी20 बैठक में भारत की अध्यक्षता में कई समाधान मिले हैं। वैश्विक समस्याओं के निराकरण पर जोर देते हुए उनके समुचित समाधान पर फोकस किया गया है। मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास पर मुहर लगी है। 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई। विकासशील देशों पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता जताई गई, ताकि कोई भी देश पीछे ना छूटे। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर बात हुई। बायो फ्यूल एलायंस बनाया जाएगा। क्रिप्टो पर पॉलिसी को लेकर भी चर्चा हुई। हमें चुनौती पूर्ण समय में अध्यक्षता मिली। निजी डेटा की सुरक्षा पर भी बात हुई। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है।

आतंकवाद पर प्रहार

37 पेजों के घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि जी20 नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की और माना कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। समिट शुरू होने से पहले ही सबकी इस पर निगाह थी कि सभी सदस्य देश संयुक्त घोषणा पत्र पर राजी होंगे या नहीं। बाली में चर्चा को याद करते हुए, हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए अपने राष्ट्रीय पदों और प्रस्तावों को दोहराया। इस बात पर जोर दिया कि सभी राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी राष्ट्रों को किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है।

21वीं सदी की चुनौतियों पर चर्चा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समिट में 21वीं सदी की चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान वैश्विक समस्याओं के निराकरण पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान क्रिप्टो के नियमन पर भी चर्चा हुई। इस बात पर चर्चा की गई कि कोई भी देश पीछे ना छूटे। इस दौरान ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। भारतीय जी-20 की अध्यक्षता ने बात को आगे बढ़ाया है। वैश्विक समाधानों की हमारी खोज में किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए।

स्वच्छ ऊर्जा पर जोर

जी20 के घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन का उल्लेख किया गया, जिसमें नेताओं ने 'कोयला आधारित बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता' पर जोर दिया। लेकिन जी20 ने तेल और गैस समेत सभी प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 85 फीसदी हिस्सा रखने वाले और 80 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जी20 की बैठक में कहा गया कि यह 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। साथ ही वह अनुपयोगी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने और तर्कसंगत बनाने के लिए 2009 में पिट्सबर्ग में किए गए अपने वादे को कायम रखेगा।

संयुक्त राष्ट्र ने दी भारत को बधाई

संयुक्त राष्ट्र ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में जी20 समूह के नेताओं द्वारा, 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' को सर्वसम्मति से पारित किए जाने का स्वागत किया यूएन महासचिव श्री एंतोनियो गुटेरेश के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने विशेष रूप से इस घोषणापत्र की भाषा का स्वागत किया है, जिसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर प्रगति की रफ़्तार में तेजी लाने पर बल दिया गया है। ■

आगे बढ़ी है भारत-सऊदी अरब साझेदारी

ब्यूरो

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज के बीच हुई बैठक के बाद भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद को काफी बढ़ावा मिला है। 11 सितंबर को हुई दोनों नेताओं के बीच बैठक में भारतीय गणराज्य और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच गहरी साझेदारी पूरी दुनिया को दिखी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में साझेदारी के महत्व पर जोर दते हुए कहा कि सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि दुनिया की दो सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जिसकी घोषणा वर्ष 2019 में उनकी सऊदी अरब यात्रा के दौरान की गई थी। बीते चार वर्षों में, यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के एक प्रभावी साधन के रूप में उभरा है।

बैठक का एक मुख्य आकर्षण भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले एक आर्थिक गलियारे की ऐतिहासिक घोषणा थी, जो सऊदी अरब से होकर गुजरेगा। गलियारा इन क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए तैयार है। नेताओं ने अपनी करीबी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने और मानवता की भलाई के लिए मिलकर काम करने की उत्सुकता जाहिर की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय समुदाय के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए प्रिंस बिन सलमान की प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रिंस बिन सलमान के नेतृत्व में हुई तीव्र आर्थिक और सामाजिक प्रगति को स्वीकार करते हुए विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की प्रगति की भी सराहना की।

इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि एजेंडे में ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति समेत कई द्विपक्षीय मुद्दे शामिल थे। दोनों नेताओं द्वारा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ बैठक संपन्न हुई। उन्होंने जी20 बैठकों में अपनी करीबी भागीदारी और जी20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता की सफलता को भी दोहराया, जिससे वैश्विक मंच पर उनके आपसी सहयोग को और अधिक बल मिला। जैसे-जैसे भारत और सऊदी अरब अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जारी रख रहे हैं, दुनिया आशा के साथ देख रही है, क्षेत्र और दुनिया के भविष्य को आकार देने में इन दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान रही है। यह द्विपक्षीय मुलाकात अधिक समृद्ध और स्थिर दुनिया के लिए मिलकर काम करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। खास बात यह भी रही कि जी20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद प्रिंस बिन सलमान भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। उनका राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया। ■

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी काउंसिल की पहली लीडर्स मीटिंग में भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दो हजार उन्नीस की मेरी सऊदी अरब यात्रा के दौरान हमने इस काउंसिल की घोषणा की थी। इन चार वर्षों में यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

हर भारतीय को श्रेय

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 की सफलता को 140 करोड़ भारतीयों की सफलता बताया है। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की यह सफलता नहीं है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की सफलता का श्रेय 140 करोड़ भारतीयों को देते हैं। आयोजन के सफल समापन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत मंडपम में जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की सफलता का श्रेय आप सभी को जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बातचीत में कहा कि आप अपने अनुभव रिकार्ड करके रखिए ताकि भविष्य में होने वाले आयोजनों में दिशा–निर्देश का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता ने देश को इस तरह के वैश्विक कार्यक्रम आयोजित करने का आत्मविश्वास दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन का प्रभाव देश की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में सफलता के रूप में सामने आया है। मेरे लिए असली खुशी इस बात में है कि मेरा देश अब आश्वस्त है कि वह ऐसे किसी भी कार्यक्रम की सर्वोत्तम संभव तरीके से मेजबानी कर सकता है।

जी20 के समापन के बाद जब संसद में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी सभी से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि हम सबके लिए गर्व की बात है, आज भारत विश्वमित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। जी20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिन्दुस्तान के अलग–अलग रंग–रूप में, देश की अलग–अलग सरकारों में बड़े आन–बान–शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्वभर के मंच पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है। देश के गौरव–गान को बढ़ाने वाला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है। और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार हैं, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है, 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। उनका यह भी कहना था कि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है, उसका उपयोग हम करने वाले हैं, और आपकी अध्यक्षता में दुनियाभर के ये जो जी20 के सदस्य हैं, पी20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट की जैसे घोषणा की, सरकार का आपके इन प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। ■

मेहमानों ने की भारत की प्रशंसा

ब्यूरो

भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और राजनयिक नई दिल्ली पहुंचे। भारत के आतिथ्य को देखकर प्रसन्न हुए। नई दिल्ली घोषणापत्र की भी सराहना की गई। वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और दक्षिण एशियाई क्षेत्र का प्रमुख स्वर बनने के लिए भारत की सराहना की।

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा कि जी20 अध्यक्ष के रूप में, भारत ने दुनिया को एकता और शांति का संदेश भेजने की पूरी कोशिश की, जबकि रूस अभी भी यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखे हुए था।

तुर्की के राष्ट्रपति श्री रजब तैयब इरदुगान ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन 'हमारे पास मौजूद एकमात्र दुनिया' के लिए एक आशीर्वाद होगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी की सराहना करते हुए **अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन** ने कहा कि अफ्रीकी संघ एक महत्वपूर्ण भागीदार है। आप (मोदी) हमें एक साथ ला रहे हैं, हमें एक साथ रख रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे पास चुनौतियों से मिलकर निपटने की क्षमता है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक ने कहा कि जी-20 नेता वित्तीय संकट के बाद वैश्विक विकास को बहाल करने के लिए 15 साल पहले पहली बार एक साथ आए थे। हम अब अत्यधिक चुनौतियों वाले समय में मिल रहे हैं। दुनिया नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक बार फिर जी-20 की ओर देख रही है। मेरा मानना है कि हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

वहीं, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक श्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा** ने कहा कि मैं एयू को इस तालिका में लाने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता के लिए आपको (मोदी) बधाई देती हूं। जी20 की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम' की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह सभी जीवन के मूल्य और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने के महत्व को कायम रखता है।

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्क रुटे ने ग्लोबल साउथ को समूह के केंद्र में रखने के लिए भारतीय राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।

विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने कहा, 'मैं भारत और उसके नेतृत्व के साथ-साथ

सभी जी20 नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई देता हूं कि इतनी शानदार घोषणा हासिल की गई।'

जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा ने जी20 को 'महान नेतृत्व' प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की सराहना की।

ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्षमता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज मैं भावुक हो गया, जब मैं प्रिय (महात्मा) गांधी को श्रद्धांजलि देने गया। मेरे राजनीतिक जीवन में गांधी जी का बहुत महत्व है। अहिंसा एक सिद्धांत है, जिसका मैं पालन करता हूं।

ओमान के अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग मामलों के उप प्रधानमंत्री श्री सैय्यद असद बिन तारिक अल सईद ने भारतीय आतिथ्य की सराहना की। आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक सुश्री गीता गोपीनाथ के अनुसार, इतने सफल जी20 की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई। भारत का 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का संदेश सभी प्रतिनिधियों के बीच मजबूती से गूंजा।

रूस के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव ने भारत के अध्यक्षता में हो रहे जी20 सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने जी20 में बहुत सफल परिणाम के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना की और इस असाधारण अवसर के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना ने शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली **स्पेन की उपराष्ट्रपति सुश्री नादिया कैल्विनो** ने भी भारत के उत्कृष्ट नेतृत्व की सराहना की और प्रधानमंत्री श्री मोदी के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की।

मैक्सिकन अर्थव्यवस्था मंत्री रकेल ब्यूनरोस्त्रो सांचेज ने जी20 के लिए अद्भुत व्यवस्था की प्रशंसा की। उनके अनुसार, भारत ने हर सुविधाओं और जरूरतों का बेहतर ख्याल रखा। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई।

कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष श्री अजाली असौमानी ने भी उनकी उम्मीदवारी के समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामफोसा ने एयू को जी20 में शामिल कराने की भूमिका के लिए भारत की सराहना की।

इटली की प्रधानमंत्री, सुश्री जियोर्जिया मेलोनी ने भारत को जी20 की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने भारत की जी20 अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि धन्यवाद, भारत। उन्होंने जी20 में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की।■

भारत का बढ़ा कद

नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन ने न केवल वैश्विक राजनयिक परिदृश्य में भारत के बढ़ते कद को उजागर किया, बल्कि त्रुटिहीन सुरक्षा और प्रशासनिक सटीकता के साथ इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया।

ब्यूरो

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर, भारत द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी राजनयिक सम्मेलनों में से एक की सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया। श्री शाह ने कहा कि यह दुनिया की विभिन्न ताकतों के बीच साल भर चली कूटनीतिक पैंतरेबाजी की परिणति थी और भारत प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने में सक्षम हुआ। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अफ्रीकी संघ को जी20 की सदस्यता दिलाने में मदद की और संदेश दिया कि भारत विकसित और विकासशील दोनों देशों के साथ है।

श्री शाह ने कहा कि शिखर सम्मेलन देश के हर उस नागरिक के लिए अमिट छाप छोड़ गया है जो भारतीय परोपकारी सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास करता है। इससे पूर्व गुरुग्राम में 'अपराध और सुरक्षा विषय' पर आयोजित जी20 के सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि भारत का जी20 अध्यक्षता का विषय-'वसुधैव कुटुम्बकम' अर्थात 'वन अर्थ' वन फैमिली 'वन फ्यूचर 'है, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह वाक्य शायद आज की 'डिजिटल दुनिया' के लिए सबसे अधिक रेलेवेंट है। श्री शाह का कहना है कि जी20 ने अब तक आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डेटा-फ्लो पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन क्राइम और सिक्यूरिटी आस्पेक्ट्स को समझना और समाधान निकालना अब बेहद आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि एनएफटी,एआई, मेटावर्स तथा अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के युग में कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव तरीके से नए और उभरते खतरों के लिए समय पर प्रतिक्रिया देकर हमें आगे रहना है। श्री शाह कहते हैं कि जी20 के मंच पर साइबर सिक्यूरिटी पर अधिक ध्यान दिए जाने से, अहम 'इनफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर' और 'डिजिटल पब्लिक प्लेटफार्मों' की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने में सकारात्मक योगदान प्राप्त हो सकता है। जी20 के मंच पर साइबर सिक्यूरिटी और साइबर क्राइम पर विचार-विमर्श करने से 'इंटेलिजेंस और इनफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क' के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में 'ग्लोबल कोऑपरेशन' को बल मिलेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जी20 के मंच पर साइबर सिक्योरिटी पर अधिक ध्यान देने से, अहम 'इनफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर' और 'डिजिटल पब्लिक प्लेटफार्मों' की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने में सकारात्मक योगदान मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जी20 के मंच पर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर विचार-विमर्श करने से 'इंटेलिजेंस और इनफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क' के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में 'ग्लोबल

हमारे जी20 अध्यक्ष पद की ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। चाहे वह नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा को अपनाना हो या अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना, शिखर सम्मेलन ने श्री मोदी जी के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के दृष्टिकोण पर खरा उतरते हुए भू-राजनीतिक क्षेत्रों के बीच विश्वास का पुल बनाया है। दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के विलक्षण महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर सभी को एकजुट करते हुए, शिखर सम्मेलन हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अमिट जीत का निशान छोड़ता है, यह हमारे उदार सांस्कृतिक मूल्यों की महानता में विश्वास को और अधिक मजबूत करता है।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

कोऑपरेशन' को बल मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त एवं सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतरराष्ट्रीय ढाँचे को बढ़ावा देना है।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रशासनिक सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी20 शिखर सम्मेलन ने न केवल वैश्विक राजनयिक परिदृश्य में भारत के बढ़ते कद को उजागर किया, बल्कि त्रुटिहीन सुरक्षा और प्रशासनिक सटीकता के साथ इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। ■

जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित

केंद्रीय कैबिनेट ने 9-10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुए जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट ने 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की थीम के विभिन्न पहलुओं को तय करने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन की सराहना की। प्रधानमंत्री के जन भागीदारी वाले दृष्टिकोण ने जी20 के कार्यक्रमों और गतिविधियों में हमारे समाज के व्यापक वर्गों को शामिल किया। 60 शहरों में हुई 200 से अधिक बैठकें, जी20 के कार्यक्रमों को लेकर लोगों की एक अभूतपूर्व भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके फलस्वरूप, जी20 की भारतीय अध्यक्षता सच्चे अर्थों में जन-केंद्रित रही और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी। कैबिनेट ने महसूस किया कि इस शिखर सम्मेलन के नतीजे परिवर्तनकारी थे और ये आने वाले दशकों में विश्व व्यवस्था को नए सिरे से आकार देने में अपना योगदान देंगे। इनमें भी सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने, हरित विकास समझौते को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया। कैबिनेट ने यह भी कहा कि ऐसे समय में जब विश्व में पूर्व और पश्चिम का ध्रुवीकरण मजबूत है और उत्तर तथा दक्षिण के बीच विभाजन गहरा है, तब प्रधानमंत्री के प्रयासों ने मौजूदा वक्त के सबसे जरूरी मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण सहमति बनाने का काम किया। केंद्रीय कैबिनेट ने जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता में शामिल सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने उस उत्साह को मान्यता दी जिसके साथ भारत के लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी ने शिखर सम्मेलन की गतिविधियों में जोर-शोर से हिस्सा लिया। कैबिनेट ने दुनिया में प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जी20 की भारतीय अध्यक्षता को एक मजबूत दिशा देने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनूठे नेतृत्व की भी प्रशंसा की।

कंधे से कंधा मिलाकर हम करते हैं काम

ब्यूरो

हाल लिया वर्षों में वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति से विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण राजनयिक आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ, जहां प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान)-भारत साझेदारी और भारत-प्रशांत क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की। 7 सितंबर को 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में भारत का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक चर्चा की और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भविष्य के लिए एक गतिशील पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया।

18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने ईएएस तंत्र के महत्व को दोहराया और इसे और मजबूती प्रदान करने में सहायता देने की फिर से पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन को रेखांकित किया तथा स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच हिंद-प्रशांत के लिए दृष्टिकोणों के तालमेल पर प्रकाश डाला और इस बात को रेखांकित किया कि आसियान क्वाड के दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से 12-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करने जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान, दो संयुक्त वक्तव्य अपनाए गए, एक समुद्री सहयोग पर केंद्रित था और दूसरा खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित था - जो क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए आसियान और भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ईएएस तंत्र के महत्व को दोहराया और भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा भोजन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की ओर से उठाए गए कदमों और आईएसए, सीडीआरआई, लाइफ और ओएसओडब्ल्यूओजी जैसी हमारी पहलों पर प्रकाश डाला। ■

खास बातें

- एक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा स्थापित करना जो दक्षिण पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप को जोड़े।
- आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करने की पेशकश।
- डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत फंड की घोषणा की गई।
- जुड़ाव बढ़ाने के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) को समर्थन के नवीनीकरण की घोषणा की गई।
- ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया।
- आसियान देशों को भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
- मिशन लाइफ पर एक साथ काम करने का आह्वान किया गया।
- जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की गई।

स्कूलों में संस्कृति और विविधता का जश्न मनाएं

ब्यूरो

शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं से बात की। प्रधानमंत्री ने बच्चों को जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों की सफलता के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 विजेताओं से मिले और उनके अनुभवों को सुना। कुल 75 पुरस्कार विजेता के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया।

प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को पोषित करने के लिए उनके अटूट समर्पण के लिए शिक्षक समुदाय की सराहना की। देश की नियति पर शिक्षकों के गहरे प्रभाव पर जोर दिया और इस प्रक्रिया में प्रेरक शिक्षकों के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही बच्चों को जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों की अविश्वसनीय सफलताओं के बारे में शिक्षित करके प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसा करते हुए, उन्होंने युवा पीढ़ी को अपनी उपलब्धियों के लिए प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए इन रोल मॉडल की अविश्वसनीय शक्ति को पहचाना। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को हमारी स्थानीय विरासत और इतिहास पर गर्व की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षकों से महान राष्ट्र की विविधता में निहित ताकत पर जोर देते हुए छात्रों को अपने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में गहराई से जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों के भीतर देश के विभिन्न हिस्सों की अनूठी सांस्कृतिक ताना-बाना का जश्न मनाकर, हम अगली पीढ़ी के बीच एकता और समझ की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। चंद्रयान-3 की हालिया सफलता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर छात्रों के बीच जिज्ञासा को और अधिक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को याद दिलाया कि 21वीं सदी निर्विवाद रूप से प्रौद्योगिकी-संचालित है और हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए इन क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल में दक्षता समय की मांग है।

प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कौशल विकास के महत्व को भी रेखांकित किया, जिससे वे तेजी से विकसित हो रही दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए भविष्य में तैयार हो सकें। उन्होंने कहा, 'हमारे युवा दिमाग को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके, हम उन्हें भारत की वृद्धि और विकास में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाते हैं।' ■

अधिक लोकोपयोगी बन रही है राजभाषा

ब्यूरो

बीते नौ वर्षों में राजभाषा हिंदी को लेकर देश में पहले से अधिक काम हो रहा है। 4 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का 12वां खंड सौंपा। इस अवसर पर संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों की भी उपस्थिति रही। साथ ही, राजभाषा को और अधिक लोकोपयोगी बनाने के विषय पर चर्चा की।

केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति जी को इस रिपोर्ट का 12वाँ खंड प्रस्तुत किया जा चुका है। 2014 तक इस रिपोर्ट के 9 खंड ही सौंपे गए थे, लेकिन हमने पिछले 4 वर्षों में ही 3 खंड प्रस्तुत किये हैं। 2019 से सभी 59 मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है तथा इनकी बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 528 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन भी किया जा चुका है। विदेशों में भी लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट-लुई में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की भी पहल की है।

श्री अमित शाह के दिशा-निर्देशन में बीते वर्षों में राजभाषा को लेकर कई काम हुए हैं। भारतीय भाषाओं के विकास को लेकर भी केंद्र सरकार कई काम कर रही है। हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इस ओर इशारा करते हुए बताया था कि राजभाषा विभाग द्वारा 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' की भी नई परम्परा शुरू की गई है। 13-14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला और 14 सितम्बर 2022 को सूरत में दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस साल पुणे में तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जिन्हें हमें साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी कोई स्पर्धा थी और न ही कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। ■

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक, प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक मिल रहा है भारतीय भाषाओं को सम्मान

14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत, विविध भाषाओं का देश रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम 'हिंदी' है।

ब्यूरो

एक भाषा के रूप में जब हम हिंदी की विकास यात्रा की बात करते हैं, तो यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। एक भाषा के विकास में उस समाज और संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां पर यह बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास में भी समाज और संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है; खासकर उत्तर भारतीय राज्यों की भूमिका। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है और इसी भाषा के विभिन्न काल खंडों में अलग-अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी का विकास हुआ है। स्वाधीनता मिलने के बाद 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। वर्ष 1953 में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव दिया तब से यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम 'हिंदी' है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी एक जनतांत्रिक भाषा रही है। इसने अलग-अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान दिया है और उनकी शब्दावलियों, पदों और व्याकरण के नियमों को अपनाया है।

14 सितंबर, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने देशवासियों को दिन विशेष की शुभकामनाएं देते हुए केंद्र सरकार द्वारा की जा रही कई पहलों की जानकारी दी। उन्होंने यह बताया कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी का वैश्विक प्रचार-प्रसार किस तरह हुआ और आधुनिक तकनीक के संग यह कैसे हर वर्ग के लिए सहज हो रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा को तकनीक के अनुसार विकसित बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण भी किया है। राजभाषा विभाग ने एक नई पहल करते हुए 'हिंदी शब्द सिंधु' शब्दकोष का भी निर्माण किया है। इस शब्दकोष में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। विभाग ने कुल 90 हजार शब्द का एक 'ई-महाशब्दकोष' मोबाइल एप्प और करीब 9 हजार वाक्य का 'ई-सरल' वाक्यकोष भी तैयार किया है। ■

भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से, सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के इन प्रयासों से सभी मातृ भाषाओं को आत्मसात करते हुए लोक-सम्मत भाषा हिंदी, विज्ञान-सम्मत और तकनीक-सम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

बीपीआरएंडडी के बिना अच्छी पुलिसिंग की कल्पना नहीं की जा सकती

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के विजन को आगे बढ़ा रहा है बीपीआरएंडडी

ब्यूरो

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक गतिशील, आधुनिक सोच एवं तकनीकी विरासत से परिपूर्ण संस्था है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दो साल पूर्व बीपीआरएंडडी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संदेश में लिखा था कि बीपीआरएंडडी के बिना अच्छी पुलिसिंग की कल्पना नहीं की जा सकती। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए बीपीआरएंडडी ने क्षमता निर्माण, आधुनिकीकरण पहल और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कारागारों एवं पुलिस बलों को समय, काल, तकनीक एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया है। जिससे ये संगठन आधुनिक भारत के सपनों को साकार करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ लोकतंत्रात्मक मूल्यों को संजोते हुए एक नागरिक केंद्रित पुलिस सेवा का निर्माण कर सकें।

बीपीआरएंडडी के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने कहा कि बीपीआरएंडडी ने पुलिस के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में एक महान भूमिका निभाई है। श्री भल्ला ने कहा कि बीपीआरएंडडी एक प्रकार का महत्वपूर्ण संगठन है, जिसके बारे में गृह मंत्रालय का मानना है कि यह वास्तव में देश में अच्छी पुलिसिंग में योगदान दे सकता है। हम में से लोग यह महसूस करते हैं कि इसे बेहतर सेवाएं देने के साथ-साथ पुलिस के प्रति लोगों की धारणा को हासिल करने की जरूरत है। पुलिसकर्मियों को ऐसे तरीके से सेवा करनी चाहिए जिसकी सराहना की जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि इस मामले में बीपीआरएंडडी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।

इस अवसर पर बीपीआरएंडडी के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव ने कहा कि हम दिन-प्रतिदिन बदल रही तकनीक के युग में जी रहे हैं और हमारे पुलिस बल भी इससे अछूते नहीं हैं। ब्यूरो का आधुनिकीकरण प्रभाग अपने विभिन्न प्रयासों से पुलिस बलों को उपयुक्त आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद कर रहा है जिससे कि वे और बेहतर हो सकें। इसके साथ ही ब्यूरो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को नीति-निर्माण में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण इनपुट दे रहा है। मुझे खुशी है कि हाल ही में, ब्यूरो के कार्यों को तब मूर्त रूप मिला जब गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आदर्श कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम 2023 को स्वीकृत कर इसे राज्यों को लागू करने हेतु भेजा। इसके अतिरिक्त जहां तक भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए बिल - भारतीय नागरिक संहिता - 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 एवं भारतीय साक्ष्य संहिता - 2023 का प्रश्न है, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इनका औपचारिक चिंतन सर्वप्रथम ब्यूरो में ही आरंभ हुआ था और आज नए भारत के निर्माण में ये बिल नए कानून का स्वरूप लेने के लिए तैयार हैं। इससे पूर्व बीपीआरएंडडी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। ■

अमृत काल में बेहतर होती सेवाएं

ब्यूरो

14 सितंबर को पुणे में तृतीय राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री मिश्रा तथा संसदीय राजभाषा समिति के संयोजक श्री रामचंद्र जांगड़ा आए और ब्यूरो के प्रकाशन की प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त हिंदी दिवस समारोह का शुभारंभ ब्यूरो मुख्यालय एवं बाह्य यूनिटों में आयोजित किया गया, जिसमें ब्यूरो के समस्त अधिकारी एवं कार्मिक शामिल हुए।

11 सितंबर को विशाखापत्तनम में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जेल प्रमुखों के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री श्रीमती तनेती विनीता, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय 'अमृत काल में कारागृह एवं सुधारात्मक सेवाएं' रखा गया। इस सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश कारागार विभाग एवं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) द्वारा किया गया।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जैसे – कैदियों की नशामुक्ति, जेलों में बंदियों का मानसिक स्वास्थ्य, सुधारात्मक प्रशासन में टेक्नोलॉजी, कारागारों में ओवरक्राउडिंग और कैद के विकल्प, जेल में महिलाएं और बच्चे– विशेष महिला जेल– : खूबियां और चुनौतियां। साथ ही समस्त प्रदेशों को ग्रुप में विभाजित कर अन्य शीर्षकों पर चर्चा हुई जैसे – जेल में उदार विचारधारा वाले धार्मिक प्रचारकों के दौरे का प्रभाव, गरीब कैदियों को समर्थन : जुमार्ना न भरना, सुधरे हुए कैदियों की लघु फिल्में।

गरीबों और वंचितों की सेवा को अपना ध्येय मानने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह सिद्ध किया है कि विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक यह समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय रक्सौल जिला में एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के कामों को लेकर जनता से संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूर्व में विकास के दिशाहीन दृष्टिकोण के चलते हमारी माताओं-बहनों को दूर-सुदूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता था। इसके विपरीत आज जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल घर-घर तक पहुंच रहा है और ग्रामीणों का जीवन सुगम हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत आज 13 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच चुका है। यह 3 से 13 करोड़ तक की यात्रा संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। गाँव हो या शहर, जल जीवन मिशन पूरे भारत के विकास को नई गति प्रदान कर रहा है।

जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई वैश्विक नेताओं से मिलने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रमाणिक ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के संदेश के साथ शानदार जी20 समिट का हिस्सा बनने पर गर्व है। नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज के दौरान भारतमंडपम में विश्व नेताओं के साथ क्षणों को साझा करने में खुशी हुई। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि वैश्विक नेता शांति के दूत महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाते हैं, जिनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके जीवनकाल के दौरान थीं। ■

वैश्विक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षण

हर्ष वी श्रृंगला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और समावेशी दृष्टिकोण के तहत भारत की जी20 अध्यक्षता एक असाधारण सफलता रही है। संकल्पना से लेकर कार्यान्वयन तक, भारत का जी20 समावेशिता, महत्वाकांक्षा, निर्णायकता और कार्य-उन्मुखता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी कल्पना प्रधानमंत्री ने तब की थी, जब पिछले साल जी20 की अध्यक्षता भारत को दी गई। भारत की अध्यक्षता ने जी20 प्रक्रिया को जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तित करने का प्रयास किया है।

भारत के नेतृत्व ने जी20 प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, वह इसे एक विशिष्ट कार्यक्रम से देशव्यापी आंदोलन में बदलना है। जैसे-जैसे यह ऐतिहासिक क्षण समाप्ति की ओर आ रहा है, हरेक को यह अनुभूति हो रही है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी का इसको लेकर दोहरा दृष्टिकोण था – जी20 प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाना और इसे विकेंद्रीकृत करना। जी20 को हरेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ले जाकर इसे पीपल्स20 में बदलने की कल्पना की। इसके अलावा, उनका मानना था कि जी20 की अध्यक्षता यह दिखाने का सही अवसर था कि भारत वैश्विक भलाई के लिए अपनी अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं को सभी के साथ साझा करे।

प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रामाणिक रूप से वास्तविकता में बदलने के लिए व्यापक और सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता है। नवीन रणनीतियों, सहकारी संघवाद की सहज सहानुभूति और विस्तृत योजना के साथ, भारत ने एक अभूतपूर्व प्रयास शुरू किया। एक समर्पित टीम द्वारा निर्देशित और क्रियान्वित, भारत ने देश भर के 60 शहरों में 200 से अधिक जी20 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित कीं। जिनमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य भी शामिल हैं, जो संभावनाओं से भरपूर हैं,हटाया जा सकता है।

यह आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित व्यापक सुरक्षा तंत्र के कारण संभव हुआ, जो जी20 बैठकों के लिए पूरी सुरक्षा की देखरेख करता था। गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने प्रतिष्ठित जी20 प्रतिनिधियों और विश्व नेताओं को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण भी दिया। जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर समन्वय ने निर्बाध तरीके से इसे सफल बनाया।

भारत की अध्यक्षता में सफल हुए जी20 शिखर सम्मेलन के जरिए भारत की क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। भारत की जी20 अध्यक्षता ने समावेशी और सहयोगात्मक कूटनीति के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। यह नेताओं के शिखर सम्मेलन में 205 महत्वपूर्ण पहलों को सर्वसम्मति से अपनाने का प्रतीक है। 83 पैराग्राफ की घोषणा सहयोग और साझा जिम्मेदारी के साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक संयुक्त प्रयास का प्रतीक है। 'वसुधैव कुटुंबकम' को आत्मसात करते हुए भारत ने अखिल विश्व के समक्ष मानव-केंद्रित वैश्वीकरण के एक ऐतिहासिक युग का उदाहरण प्रस्तुत किया।

अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पहल 'एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा' शीर्षक से साइबर-सुरक्षा पर पहला जी20 सम्मेलन आयोजित करना था। साइबर सुरक्षा उपायों पर केंद्रित इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री का कहना है कि साइबर-सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा-वैश्विक सुरक्षा का विषय बन गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य 'डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं' और 'डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे' को सशक्त बनाने और सुरक्षित करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की शक्ति का इष्टतम उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और कुशल अंतरराष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना था।

भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण पारंपरिक कूटनीति से आगे निकल गया और पीपल्स20 के उनके दृष्टिकोण को 'जनभागीदारी' की अनूठी अवधारणा के माध्यम से साकार किया गया। भारत में 1.5 करोड़ से अधिक नागरिकों और विश्व स्तर पर 45 लाख से अधिक नागरिकों ने जागरूकता रैलियों, प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और स्वच्छता अभियानों सहित जी20 से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस व्यापक जुड़ाव के कारण भारत के जी20 के अभियानों को बेहद लोकप्रियता मिली। भारत के झंडे के रंग, कमल और पर्यावरण-चेतना से प्रेरित जी20 लोगो, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया, जिसे भारत और विदेश दोनों में मान्यता मिली। वैश्विक भलाई के लिए पर्याप्त प्रगति करने का यह अनूठा दृष्टिकोण भारत की अध्यक्षीय विरासत है।

इस परिवर्तनकारी यात्रा में, एक वैश्विक नेता के रूप में भारत का उत्थान न केवल प्रतिष्ठा का विषय है, बल्कि सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम उन शहरों, देशों और महाद्वीपों से कहीं अधिक हैं जो हमें विभाजित करते हैं। हम वास्तव में 'एक पृथ्वी' पर 'एक भविष्य' के साथ 'एक परिवार' हैं और हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। ■

(लेखक जी20 के मुख्य समन्वयक, पूर्व विदेश सचिव एवं पूर्व राजदूत संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।)

जी20 शिखर सम्मेलन से पहले एनएसजी की एरियल इंसर्शन टीम ने महत्वपूर्ण ऊंची इमारतों पर सटीक स्पॉट एरियल ड्रॉप करके आतंकी हमलों की स्थिति में मुकाबला करने के लिए तीसरी आयामी त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास किया।

पुणे में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के दौरान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने स्टॉल लगाया। 15 सितंबर को केरल के राज्यपाल, महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद ने इसका अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्हें ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 'सजग भारत' की अद्यतन प्रति भेंट की गई।

नई दिल्ली में 12 सितंबर को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री नितिन अग्रवाल ने माउंट मनास्लू के लिए बीएसएफ पर्वतारोहण अभियान-2023 की शुरुआत की घोषणा की और मुख्यालय में औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई। माउंट मनास्लू, समुद्र तल से 8,163 मीटर (26,775 फीट) ऊपर दुनिया के आठवें सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में खड़ा है। यह नेपाल के पश्चिम-मध्य क्षेत्र में मानसिरी हिमाल में है। इस अभियान का उद्देश्य है -'आत्मा के पर्वत' को श्रद्धांजलि अर्पित करना और 'स्वच्छ हिमालय - ग्लेशियर बचाएं' और 'हम फिट है तो इंडिया फिट' अभियान का नेतृत्व करना।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 'पुलिस और सेवा' अभियान के तहत डीएसपी पालमपुर, श्री अमित शर्मा ने बताया कि सड़क के संकेतों को समझना, पढ़ाई-लिखाई के लिए एबीसी...या अ आ...जैसा। उन्होंने बताया कि सड़क के संकेत प्रमुख रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ये है मैनड्रेटरी, कॉशनेरी और इंफॉमेटरी। अंत में उन्होंने संदेश दिया कि वाहन चलाते समय सड़क के संकेतों का ध्यान रखें, सड़क पर सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

(Photos Link X.Com)

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि.,नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

हर व्यक्ति को देश के भविष्य के साथ जोड़ना, उसकी भावनाओं को देश की प्रगति के साथ जोड़ना और हर व्यक्ति के पुरुषार्थ को देश के उत्कर्ष और विकास के साथ जोड़ना ही नेतृत्व की कसौटी और इसका दायित्व होता है। पूरा देश भाग्यशाली है कि बहुत समय के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के रूप में हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो आजादी के अमृत महोत्सव में देश को विश्व में सर्वप्रथम बनाने वाले रास्ते पर प्रशस्त कर रहा है।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली-110037